21-02-2024

देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य इस केंद्र के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है | इसके माध्यम से नौकरी की भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्र का नेतृत्व करके, अमृत पीढी के कौशल-समूह को मांग-संचालित उद्योगों में उन्नत किया जाएगा |
- यह पहल मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन और आतिथ्य, और आईटी-आईटीईएस जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में युवा शक्ति की क्षमताओं और ज्ञान का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- यह एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो कक्षा और कार्य-आधारित शिक्षा के एक अद्वितीय संयोजन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल के साथ सशक्त बनाता है।
- यह केंद्र सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो औपचारिक कौशल की मांग की पूर्ति करेगा और युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।
- कौशल भारत केंद्र (एसआईसी) उद्योग विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो उद्योग की बदलती अवश्यकताओं के अनुरूप होगा, मानकीकरण को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जो उद्योगों में कुशल प्रतिभा की मांग को पूरा करेगा।
- यह युवाओं के लिए एक उल्लेखनीय अवसर है

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

जिसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने के अनुभव प्राप्त करना और प्रसिद्ध संगठनों के साथ संभावित कैरियर के रास्ते तलाशना है।

- इस कार्यक्रम के बाद, ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है।
- ध्यान रहे, वर्ष की शुरुआत में कौशल रथ पहल शुरू की गई थी, जो ओडिशा के संबलपुर, अंगुल और देवगढ़ जिलों में इच्छुक उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई बसें हैं। इसने पहले ही 4000 उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रम मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे डिजिटल साक्षरता, खुदरा और उद्यमशीलता कौशल और क्षेत्र के समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिला है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बारे में

- एनएसडीसी की स्थापना वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कौशल विकास में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देने और लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था।
- यह नेशनल स्किलिंग मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाना था।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) देश में कौशल इकोसिस्टम का प्रमुख वास्तुकार है। यह भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत काम करने वाला एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) उद्यम है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कौशल इकोसिस्टम को तैयार करने और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल बनाने के लिए कौशल भारत मिशन के रणनीतिक कार्यान्वयन और ज्ञान भागीदार बनने के लिए की गई थी।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) उन उद्यमों, स्टार्ट-अप, कंपनियों और संगठनों को सहायता प्रदान करता है जो संभावित कार्यबल को भविष्य के कौशल में अवसरों की दुनिया की पेशकश करके प्रभाव पैदा कर रहे हैं।
- संगठन पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता, उम्मीदवारों को रियायती ऋण के साथ-साथ अन्य नवीन वित्तीय उत्पादों और रणनीतिक साझेदारी के निर्माण की पेशकश करके कौशल में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाने, समर्थन और समन्वय करने के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करता है।

CMS के पक्षकारों का 14वाँ सम्मेलन (COP-14)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS 14) के लिये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (CoP) की चौदहवीं बैठक का आयोजन समरकंद, उज़्बेकिस्तान में किया गया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- बैठक में पक्षकारों ने 14 प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के संबद्ध में लिस्टिंग / सूचीबद्धता प्रस्तावों को अपनाने पर सहमति जताई|

- इन प्रवासी प्रजातियों में यूरेशियन लिंक्स, पेरूवियन पेलिकन, पल्लास की बिल्ली, गुआनाको, लाहिले की बॉटलनोज़ डॉल्फिन, हार्बर पोरपोइज़, मैगेलैनिक प्लोवर, बियर्डेड वल्चर, ब्लैकचिन गिटारफिश, बुल रे, लुसिटानियन काउनोस रे, गिल्डेड कैटफिश और लौलाओ कैटफिश शामिल हैं।
- प्रस्तावों में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी खतरों का समाधान करने, शोध करने और संरक्षण नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये रेंज राज्यों (Range States) के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया। विदित है कि रेंज राज्य का आशय उन देशों अथवा क्षेत्रों से है जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं जहाँ एक विशेष प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ये देश अथवा क्षेत्र प्रजातियों और उनके आवास के प्रबंधन, संरक्षण तथा सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।
- बैठक में प्रवासी प्रजातियों के मौजूदा विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें निवास स्थान का क्षरण, विखंडन, अवैध व्यापार, बायकैच, संदूषक और कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे फेंसिंग, तेल तथा गैस हेतु पर्यावरण का ह्रास, खनन एवं जल के भीतर ध्वनि जैसी मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं।

CMS क्या है?

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतरसरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
- इस संधि पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह वर्ष 1983 से लागू है। विदित है कि 1 मार्च 2022 तक, CMS में 133 पार्टियाँ/राष्ट्र सम्मिलित हुए हैं। भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक सदस्य रहा है।
- इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना है। यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिये कानूनी आधार तैयार करता है।
- CMS के अंतर्गत दो परिशिष्ट - परिशिष्ट I ('संकटापन्न प्रवासी प्रजातियाँ') और परिशिष्ट II ('अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों') की सूची दी गई है।
- CMS के अंतर्गत भारत ने कुछ प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये गैर-बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर भी किये हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डूगोंग (2008) और रैप्टर (2016) शामिल हैं।
- गौरतलब है कि भारत, विश्व के 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्विक जैवविविधता में लगभग 8% का योगदान देता है। भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है जिनमें अमूर फाल्कन, बार-हेडेड गीज़, ब्लैक-नेक्ड क्रेन, समुद्री कछुए, डुगोंग, हंपबैक व्हेल आदि शामिल हैं।

i-ऑन्कोलॉजी AI प्रोजेक्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने "i-

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

ऑन्कोलॉजी AI प्रोजेक्ट" नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित मॉडल विकसित किया है जिसमें एक सुपर कंप्यूटर एकीकृत किया गया है।

- यह मॉडल ऑन्कोलॉजिस्टों को कैंसर के उपचार के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करेगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस प्रोजेक्ट को AIIMS, दिल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), पुणे तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त प्रयसों द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य AI का उपयोग कर कैंसर के उपचार की सटीकता और प्रभावकारिता बढ़ाना है और साथ ही आनुवंशिक प्रोफाइल, नैदानिक इतिहास और उपचार परिणामों को शामिल करने वाले व्यापक डेटासेट का विश्लेषण कर आनुवंशिकी तथा कैंसर चिकित्सा की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करना है।
- यह प्लेटफॉर्म रक्त परीक्षण, लैब रिपोर्ट, स्कैन एवं रोगी के रिकॉर्ड सहित कैंसर से संबंधित विभिन्न डेटा को संग्रहीत करने के साथ-साथ विश्लेषण भी करता है।
- उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, AI-सक्षम प्लेटफॉर्म डॉक्टरों को व्यापक जीनोमिक डेटा विश्लेषण के आधार पर उपचार निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे रोगियों के लिये उपचार योजना तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है।
- भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट तथा डिम्बग्रंथि कैंसर की व्यापकता को देखते हुए, i-ऑन्कोलॉजी, AI का प्रारंभिक अनुप्रयोग इन कैंसर का शीघ्र पता लगाने पर केंद्रित है।

कैंसर क्या होता है?

- कैंसर रोगों का एक जटिल समूह है जो शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार के रूप में पहचाना जाता है।
- कैंसर कोशिकाएँ स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर सकती हैं।
- एक स्वस्थ शरीर में, कोशिकाएँ विनियमित रूप से बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं व नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कैंसर के मामले में, आनुवंशिक उत्परिवर्तन इस सामान्य कोशिका चक्र को बाधित करते हैं, जिससे अनियंत्रित वृद्धि होती है और ट्यूमर का निर्माण हो सकता है।
- ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी (GLOBOCAN) के वर्ष 2020 के अनुमान के अनुसार विश्व भर में 19.3 मिलियन कैंसर के मामले सामने आए हैं, जिसमें भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।
- लैंसेट के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मामलों में 57.5% की वृद्धि होगी, जो 2.08 मिलियन तक पहुँच जाएगी। अकेले वर्ष 2022 में, कैंसर से, मुख्य रूप से देर से पता चलने के कारण भारत में 8 लाख से अधिक मौतें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप जीवित रहने की दर केवल 20% थी।

जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा के कोरापुट ज़िले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) घोषित किया गया है। इससे पहले ओडिशा के तीन क्षेत्रों मंदसरू, महेंद्रगिरि और गंधमर्दन को जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) के रूप में घोषित किया गया है।
- यह वन 350 हेक्टेयर के सीमांकित क्षेत्र को कवर करता है और जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

पारंपरिक रूप से पूजनीय अपने पवित्र उपवनों के साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्त्व है।

- यह वन स्तनधारियों की 28 प्रजातियों सहित कम-से-कम 608 जैव प्रजातियों का निवास स्थान है। इन प्रजातियों में मगरमच्छ, कांगेर घाटी रॉक गेको, सेक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग और विभिन्न पक्षी जैसे काला बाजा, जेर्डन बाजा, मालाबेर ट्रोगोन, आम पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाले कठफोड़वा और बैंडेड बे कोयल शामिल हैं।

जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) क्या है?

- जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें अनूठे, सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैवविविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ-साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त, कीस्टोन प्रजाति पाई जाती हैं।
- जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय-समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैवविविधता के महत्त्व के क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
- जैवविविधता विरासत स्थल (BHS) के निर्माण से स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर उनके द्वारा स्वेच्छा से तय की गई प्रथाओं के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैवविविधता विरासत स्थल था, जिसे वर्ष 2007 में जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 जैवविविधता विरासत स्थल मौजूद हैं।

जूट उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति ने 'जूट उद्योग के विकास तथा संवर्द्धन' पर 53वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। लगभग 73% जूट उद्योग का केंद्र (कुल 108 जूट मिलों में से 79) पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
- यह एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद होने के कारण 'सुरक्षित' पैकेजिंग के सभी मानकों को पूरा करता है।
- भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन में 70% का योगदान देता है। जूट उद्योग प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 3.7 लाख श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करता है|
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में कुल 1,246,500 मीट्रिक टन (MT) के साथ महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।
- जूट से निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 177,270 मीट्रिक टन हो गया, जो कुल उत्पादन का लगभग 14% है। यह वर्ष 2019-20 के निर्यात के आँकड़ों की तुलना में 56% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- इसी अवधि में भारत ने 121.26 हज़ार मीट्रिक टन कच्चे जूट का आयात किया। उच्च गुणवत्ता वाले जूट की मांग के कारण बांग्लादेश से जूट का आयात किया गया है।

जूट के बारे में

- जूट एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल कृषि उत्पाद है|
- जूट की कृषि के लिये तापमान : 25-35°C के बीच, वर्षा लगभग 150-250 सेमी. एवं जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है|
- भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। लेकिन जूट मीलों की सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश में स्थित है|
- जूट की कृषि तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में केंद्रित है, जो उत्पादन का 99% हिस्सा है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी पर केंद्रित है।
- बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णियाँ जिला में होता है|
- जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग जूट की थैली, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)